1914. [*Transferred to the 30th May*, 1990]

खाद्यान्न उत्पादन

1915. **सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने 1990-91 के वर्ष के लिए खाद्यान्न के उत्पादन के लिए 176.5 मिलियन टन का लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) क्या लक्ष्य पिछले वर्ष के खाद्यान्न उत्पादन के लक्ष्य से केवल 0.8 प्रतिशत अधिक है;

(ग) क्या यह भी सच है कि कृषि नीतियों और कार्यक्रमों संबंधी उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा है कि खाद्यान्न उत्पादन में 4.7 प्रतिशत की वृद्धि होना अनिवार्य है; और

(घ) यदि हां, तो खाद्यान्न उत्पादन के कार्यक्रम समिति की सिफारिश के अनुसार न तैयार किए जाने के क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नितिश कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) 1989-90 के दौरान 170-173 मिलियन मीटरी टन के अनुमानित उत्पादन की तुलना में परिकल्पित वृद्धि 2.0-3.8 प्रतिशत के बीच होगी।

(ग) और (घ) श्री भानु प्रताप सिंह की अध्यक्षता में गठित की गई कृषि नीति और कार्यक्रमों संबंधी उच्च शक्ति प्राप्त समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत नहीं की है।

पंजाब में युवाओं के लिए विशेष रोजगार कार्यक्रम

1916. **सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने पंजाब में, और विशेष रूप से सीमावर्ती जिलों में 15 से 20 वर्ष की आयु के युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार इस कार्यक्रम को कब तक कार्यान्वित करने का विचार रखती है?

श्रम और कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार, पंजाब सरकार ने एक योजना तैयार की है जो गुरदास पुर, फिरोजपुर तथा अमृतसर के सीमावर्ती जिलों में 16 किलोमीटर के सीमावर्ती क्षेत्र से 16 से 20 वर्ष के आयु वर्ग के युवाओं को रोजगार प्रदान करेगी। चुने हुए व्यक्तियों को राशन के लिए धन तथा जेब खर्च दिया जाएगा तथा कम्पों में रखा जाएगा और प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्हें तत्पश्चात या तो पुलिस, होमगार्ड अथवा अन्य सरकारी नौकरियों में समविष्ट करने के प्रयास किए जाएंगे अथवा उन्हें अपने स्वयं के लघु एकक/उद्यम स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना में लगभग 10,000 युवा व्यक्ति शामिल किए जाएंगे।

त्रिलोकपुरी, दिल्ली में मकानों का आबंटन

1917. **डा० जितेन्द्र कुमार जैन :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा त्रिलोकपुरी में बनाये गये लगभग 300 मकान खाली पड़े हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इन मकानों को पात्र व्यक्तियों को आवंटित न किये जाने के क्या कारण हैं;

(ग) इन मकानों के निर्माण का कार्य किस तारीख को आरंभ हुआ था और किस तारीख को पूरा हुआ; और

(घ) क्या यह भी सच है कि निर्माण में विलम्ब हो जाने के कारण इन मकानों की लागत बढ़ गई है, यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी, हां।

(ख) और (घ) त्रिलोकपुरी, पाकेट "बी" में बनाए गए 339 फ्लैट 27.3.89 को आबंटित किए गए थे। तथापि, अन्तिम मांग पत्र जारी नहीं किए जा सके क्योंकि, इन फ्लैटों की कीमत को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

(ग) इन फ्लैटों का निर्माण विभिन्न आवास योजनाओं के अंतर्गत 1980 से 1988 की अवधि के दौरान अलग-अलग समय पर किया गया था। निर्माण पूरा करने के लिए सामान्यतः 3 से 4 वर्ष का समय लगता है।

Over-crowd at New Delhi Railway Station

1918. SHRI SYED SIBTEY RAZI: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether the entry to New Delhi Railway Station from Gate No. 1 through Chelmsford Road is always crowded;

(b) whether this over-crowd is due to Amrit Kaur Market shops;

(c) whether these shops are under jurisdiction of Railways;

(d) whether the Railways proposes to take some concrete steps in the regard in consultation with local different agencies; and

(e) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI AJAY SINGH): (a) and (b) Yes, Sir.

(c) The shops are located on Railway land under licence to the Municipal Corporation of Delhi.

(d) Yes, Sir.

(e) The Municipal Corporation of Delhi and the Delhi Administration have been requested to hand over vacant possession of the land to the Railways, for taking up improvement to the circulating area in front of New Dehi Railway Station. A Committee of representatives of the Railways, Municipal Corporation of Delhi and Delhi Development Authority has been set up to prepare a scheme for development of this area.

Concession of railway facilities to the Officials of the Railways coming from far off areas

1919. SHRI SYED SIBTEY RAZI: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) Whether some officials of the rank of Section Officers and above of the Ministry are attending their offices from Ghaziabad, Faridabad, Meerut, Ballabgarh and Bahadurgarh daily;

(b) Whether these officers are enjoying the facility of concessional monthly railway tickets;

(c) Whether these officers have been allotted general pool accommodation;

(d) if so, whether Government propose to take some concrete steps to check the said irregularities being Committed by them; and

(e) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?